



मेक इन इंडिया के साथ रोजगार अवसर

¹डॉ० राम शंकर पाण्डेय एवं ²मुस्कान गुप्ता
¹असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, ²एम.ए. अर्थशास्त्र
 एस.एस. कॉलेज शाहजहाँपुर

शोध सार : भारत सरकार का अभियान मेक इन इंडिया जिसका अर्थ “ भारत में बनाओ” इसको भारत सरकार ने 25 सितम्बर 2014 को देश में लागू किया है। भारत सरकार का लक्ष्य भारत को ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग हब (वैश्विक विनिर्माण) बनाना है। इस अभियान के तहत जनता को विनिर्माण के लिए प्रोत्साहित करना है, कंपनियों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहन देना है। निवेश को बढ़ावा देना, देश में विश्व स्तर पर निर्माण कार्य के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई पहल है, जिसने भारतीय व्यापार नीति को और आसान बना दिया है। मेक इन इंडिया के अन्तर्गत रोजगार देन, प्रौद्योगिकी और निवेश के रूप में विदेशी कंपनियों को निमंत्रण देना भूमि का ‘उपयोग करके देश के विकास कार्यों में लगाना है।

मेक इन इंडिया का नेतृत्व उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है मेक इन इंडिया के तहत भारत सरकार का लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करना है तथा निवेशकों को नियंत्रित आर्थिक विकास करना है वर्ष 2022 तक मेक इन इंडिया के अन्तर्गत लगभग 25 क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त की गई है। हम कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया अभियान भारत

सरकार द्वारा देश के आर्थिक विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए चलाई गई पहल है जिसमें घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है, रोजगार के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं और विदेशी कंपनियों को भी निवेश के लिए आकर्षित किया जा रहा है। मेक इन इंडिया भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

प्रमुख शब्द: मैन्युफैक्चरिंग, प्रौद्योगिकी, निवेशक, विनिर्माण, वाणिज्य, उद्यमशीलता, जीडीपी, स्मार्ट सिटी, नेट बैंकिंग।

प्रस्तावना : मेक इन इंडिया अभियान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्ष 2014 में चलाया गया है, जिसके तहत भारत को वैश्विक विनिर्माण का हल बनाना है तथा जनता को रोजगार प्रदान करना है। मेक इन इंडिया के तहत देश की उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। जिसमे भारत सरकार का लक्ष्य विनिर्माण क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि को 12-14 प्रतिशत करना है। भारत में विदेशी निवेशको में चीन, जापान, फ्रांस, दक्षिण कोरिया आदि ने भारत की उद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अपनी रुचि दिखाई है तथा निवेश करने के लिए पहल की है।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के तहत इस अभियान को लागू किया गया है जिसमें भारत में व्यापार करने के तरीके को सरल बनाया गया है कई लाइसेंस की छूट दी गई है। तथा विदेशी एवं घरेलू निवेशकों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया गया है। मेक इन इंडिया के प्रयास से ही भारत विश्व में तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है।

मेक इन इंडिया के उद्देश्य :

भारत सरकार द्वारा इस अभियान का उद्देश्य देश का आर्थिक विकास करना तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है इसके तहत मेक इन इंडिया मिशन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

(क) भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में विनिर्माण बढ़ाना ।

(ख) भारतीय अर्थव्यवस्था को ग्लोबल मैनुफैचरिंग हब बनाना ।

(ग) नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना विकास को बढ़ावा देना ।

(घ) सतत भारत में व्यापार व्यवस्था में सुधार करना ।

(ङ) विदेशी निवेशकों को आकृषित कर निवेश के लिए प्रोत्साहित करना ।

(च) विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना ।

इस शोध में सरकार मेक इन इंडिया के तहत भारत में रोजगार सृजित करना तथा विनिर्माण करना, निवेश करना है जिससे कि भारत की जीडीपी बढ़े, भारत का आर्थिक विकास हो। मेक इन इंडिया के तहत न केवल तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी माध्यम से विकास की राह चुनी गई है बल्कि इसमें देश के प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए अनेक कार्य किये गए हैं ।

मेक इन इंडिया के अन्तर्गत 25 क्षेत्रों को उपलब्धि प्राप्त हुई है जिसमें लगभग 300 कम्पनियों को जोड़ने की योजना है। तथा इससे 2022 तक भारत में 100 मिलियन से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना है। हमने इस अध्ययन में योजना एवं कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका, समाचार पत्रों, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनोमिक टाइम्स से प्राप्त जानकारी सम्मिलित है ।

भारतीय अर्थव्यवस्था में मेक इन इंडिया की भूमिका:—

मेक इन इंडिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत नेट बैंकिंग, डिजिटलीकरण एवं तकनीकी क्षेत्र में विकास कर रहा है। मेक इन इंडिया के तहत सरकार ने अनेक प्रयास किये हैं, जिससे निर्माण क्षेत्र में अनेक सुधार हुए हैं सरकार और जनता के मध्य उद्योगों के लिए साझेदारी हुई है तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया गया है। सरकार प्रौद्योगिक और तकनीकी विकास के अन्तर्गत स्मार्ट सिटी का निर्माण कर रही है। सरकार ने व्यापारियों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया सरल बनाई। सरकार ने एफडीआई की सीमा को 100 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है जिसमें सरकार ने एफडीआई को 26 से 49 प्रतिशत तक और बढ़ाया है। इससे सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 15–16 से बढ़कर 2025 तक 25 प्रतिशत होने की उम्मीद है इनके तहत मेक इन इंडिया मिशन का कार्य न केवल विनिर्माण करना बल्कि अन्य क्षेत्रों को भी बढ़ावा देने का है। मेक इन इंडिया के तहत स्कीम एवं योजनाएँ निम्न हैं:—

- राष्ट्रीय तकनीकी वस्तु मिशन
- इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण की योजना
- बाजार संवर्धन और विकास योजना।
- निर्यात बाजार संवर्धन

पारम्परिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष की संशोधित योजना इन योजनाओं के माध्यम से सरकार पूरे भारत में मेक इन इंडिया मिशन को लागू करके पूरे देश को लाभान्वित करना चाहती है। सरकार विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित कर रही, घरेलू निर्माण पर ध्यान दे रही तथा विदेशी निवेशकों को भी प्रोत्साहित कर रही है। मेक इन इंडिया के 2014–15

और 2019–2020 में विनिर्माण की विकास दर 6.9 प्रतिशत थी जो कि अभी तेजी से विकसित हो रही है।

मेक इन इंडिया मिशन का प्रभाव :-

मेक इन इंडिया मिशन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ प्राप्त हुआ। भारत पूरी दुनिया में एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में अपना नाम बना रहा है। इस मिशन के तहत भारत ने स्मार्ट सिटी का विकास किया है नेट बैंकिंग के माध्यम से विकास तथा विनिर्माण के साथ-साथ अन्य विदेशियों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

आज इस मिशन को लगभग दस वर्ष होने को आये हैं जिसमें भारत की जीडीपी बढ़ी है तथा विदेशी मुद्रा भण्डार में 6.3 बिलियन की बढ़ोतरी भी हुई। जिससे विदेशी मुद्रा भण्डार लगभग 7 जून 2023 तक 586.41 बिलियन के स्थान पर पहुँच गया है।

उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने मेक इन इंडिया मिशन को यूपी मिशन के रूप में प्रदेश में लागू किया है जिसमें मुख्यमंत्री ने लगभग 20 करोड़ रुपये को प्रदेश के विकास के लिए लगाया।

मेक इन यूपी मिशन के अन्तर्गत प्रदेश की सरकार प्रत्येक उद्योग को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। जिसके लिए सरकार ने (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत प्रदेश का विकास का लक्ष्य तैयार किया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 90 लाख सक्रिय एमएसएमई है जिसमें 3.9 करोड़ लोग कार्यरत हैं। यूपी में एमएसएमई का 14 प्रतिशत हिस्सा है जो कि पूरे देश का 10 प्रतिशत शामिल है। जिसके लिए 2022 वित्त वर्ष में योगी आदित्यनाथ ने 1.10 करोड़ रुपये का निवेश किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेक इन इंडिया और इवेस्ट इन इंडिया के तहत विदेशी कंपनियों को आकर्षित किया है, हाल ही में हुई

जी.-20 की बैठक में अनेक विदेशी कम्पनियों ने उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए निवेश किया है।

प्रदेश में सरकार ने मेक इन इंडिया के माध्यम से मेक इन यूपी मिशन के तहत प्रदेश के विकास के लिए विनिर्माण, व्यवसाय, निवेश आदि के क्षेत्र पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है जिससे न केवल प्रदेश का बल्कि पूरे भारत का विकास हुआ है।

जिला शाहजहापुर में मिशन मेक इन इंडिया के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार ने 152.43 करोड़ की लागत के साथ 53 परियोजनाओं का शुभारम्भ किया है। सरकार ने जिले की नदियों पर 80 करोड़ रुपये पुल बनवाने के लिए भी आवंटित किये हैं जिससे कि जिला के लोगों को रोजगार मिलेगा साथ ही साथ विकास भी होगा।

सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद के तहत यहाँ के कई लघु उद्योगों का विकास किया है जिसके अन्तर्गत जरी जरदोजी, कालीन निर्माण, कृषि आधारित व्यापार पर भी व्यय किया गया है और इनको देश विदेश में भी निर्यात किया जा रहा है जिससे कि विदेशी निवेशक आकर्षित होकर यहाँ निवेश कर जिला का विकास करने में सहयोगी बन रहे हैं।

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रदेश की सरकार ने 152.43 करोड़ का निवेश रोजगार देने तथा प्रदेश की उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए किया है। जिसमें प्रदेश की सरकार ने जिला में सीएनजी गैस एजेन्सी, कृभको, रिलायंस थर्मल पॉवर खाद फ़ैक्ट्री, चीनी फ़ैक्ट्री आदि के साथ-साथ लघु एवं कुटीर उद्योगों पर ध्यान दिया है। जिससे शाहजहाँपुर के साथ प्रदेश का विकास सम्भव हुआ है एवं भारत की अर्थव्यवस्था पर भी अच्छा प्रभाव दिखाई दे रहा है।

मेक इन इंडिया के तहत चुनौतियाँ:-

मेक इन इंडिया के तहत भारत सरकार और जनता दोनों के ही अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके तहत इस मिशन को पूरा करने में अनेक समस्याएँ हैं—

- अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे की समस्या ।
- कौशल विकास का अभाव ।
- जटिल नियामक प्रक्रियाओं का होना ।
- लालफीताशाही ।
- भ्रष्टाचार की समस्या ।
- रोजगार में देरी होना ।
- पूंजी की ऊंची लागत ।

आगे की दिशा:—

- भारत की वर्तमान, अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत विश्व में पांचवे स्थान पर है, जो कि सरकार को चाहिए की वह और अधिक से अधिक देश का विकास करे ।
- आने वाले समय में जनसंख्या नियंत्रण के माध्यम से विकास करने का लक्ष्य है ।
- घरेलू विनिर्माण के साथ-साथ विदेशी निवेशकों को भी प्रोत्साहित करना ।
- इस पहल के माध्यम से भारतीय व्यवसायों का लक्ष्य है कि जो उत्पाद मेड इन इंडिया” है वह “मेड फॉर वर्ल्ड हो जिससे भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व की सामने अपनी छवि प्रस्तुत करेगा ।

निष्कर्ष : मेक इन इंडिया 25 सितम्बर 2014 को नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रारम्भ की गई पहल है जिसमें अनेक क्षेत्रों को शामिल किया है जो अनेक क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा दे रहा

हैं मेक इन इण्डिया के चार स्तभ नई मानसिकता, नये क्षेत्र नया बुनियादी ढांचा और नई प्रक्रियाएँ हैं मेक इन इण्डिया के लिए सिंह लोगो का चयन किया गया है जिसका मतलब साहस तागत और बुधिमता हैं। मेक इन इण्डिया के कारण भारत में विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के साथ एफडीआई में भी बढ़ोत्तरी होगी।

सन्दर्भ सूची :-

1. भारत में उद्यमिता:- कलराज मिश्रा।
2. डिजिटल इण्डिया और भारत- विराग गुप्ता।
3. समर्थ भारत- पंकज कुमार सिंह।
4. परिवर्तन की ओर- शिवानन्द द्विवेदी।
5. मोदी है तो मुमकिन है- महेश दत्त शर्मा।
6. नरेन्द्र मोदी के पांच प्रण- हिमाशुं कुमार।
7. निबन्ध निकुंज- डॉ. मनीष रज्जंन।
8. 21वीं सदी में एवं कदम आत्मनिर्भर की ओर भारत- डॉ. सन्तोष कुमार उपाध्याय, धनंजय देव पाण्डेय।
9. नरेन्द्र मोदी का सैन्य प्रेम- महेश दत्त।
10. कुरुक्षेत्र फरवरी 2022।
11. प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकी 2015।